7.00 P.M.

आधारभूत संरचनाएं हैं, उनका समुचित दोहन किया जाए। इसी सुझाव के तहत मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि वह पटना में 80 एकड़ में फैले और स्वयं के निर्मित भवन में कई वर्षों से चल रहे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.एम.एस.) में 100 छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति प्रदान करे। साथ ही, बिहार के अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों, यथा पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज आदि में प्रत्येक में 50-50 सीटें बढ़ाई जाए, जिससे बिहार के छात्रों को इस प्रयोजनार्थ अन्यत्र न भटकना पड़े और इस देश में चिकित्सकों की जो कमी है, उसकी भी भरपाई हो सके। सदन में प्रतिपक्ष के नेता भी अरुण जेटली ने भी स्वास्थ्य परिचर्चा में भाग लेते हुए इस आशय का वक्तव्य दिया था।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : सर, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

Demand to stop supply of ready to use therapeutic foods in the country

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, I would like to draw your attention to the recent information that international agencies like UNICEF have been importing some kind of branded 'Ready to Use Therapeutic Foods' for the treatment of severely malnourished children and this has been used and distributed without the permission of the Government of India. This is highly objectionable.

International agencies and vested interests are attempting to push these foods in contravention of the Government policy. I believe that indiscriminate distribution of such foods will commercialize young child feeding through market driven approaches. This would change the feeding patterns of young children in the villages and simplify the management of malnutrition. This will also destroy local solutions developed by the people; even the Indian Academy of Pediatrics recommends a modified family pot approach for this.

The Government of India's letter no. Z-28020/50/2003-CH, Ministry of Health and Family Welfare stated as follows:

"The Ready to Use Therapeutic Foods is plum peanut, from France @ US $ 60 per child. RUTFs are not an accepted strategy of the Government of India, neither under RCH nor ICDS."

I am astonished how this food were procured and distributed by UNICEF in some of the States without any knowledge or approval of the Ministry of Women and Child Development, Government of India.

I demand that this RUTF procurement and supply should immediately be stopped.

Demand to take steps to facilitate early construction of Dadri Power Project in Uttar Pradesh

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरा Special Mention UP में power crises और shortage से मुताल्लिक है।

सर, 21 जुलाई को हिन्दुस्तान टाइम्स में इश्तिहार के ज़रिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सारे पावर प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा दिया है। इस पत्र में दादरी पावर प्रोजेक्ट का नाम-ओ-निशां नहीं है। 2003 में सरकार ने 2500 एकड़ किसानों की उपजाऊ ज़मीन उनसे हासिल करके कम्पनी को उपलब्ध करा दी थी। आज 2009 में यह प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर ही है। किसानों का बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था और वे जेल भी